International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 02, February 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जिया-उल-हक़और परवेज़ मुशर्रफ़ के सैनिक शासनकाल मेंपाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी

शिम्पी पान्डे*

सार: पाकिस्तान की राजनीति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यहाँ धर्म और राजनीति का अनूठा संगम पाया जाता हैIसैय्यद मौलाना अबुल अला मौदूदीद्वारा स्थापित जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान में एक प्रमुख धार्मिक-राजनीतिक दल है जो पाकिस्तान में इस्लामिक मूल्यों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रसिद्ध है व पाकिस्तान की राजनीति में इस्लामिक मूल्यों बढ़ावा देने की पक्षधर हैI जमात-ए-इस्लामी मात्र एक धार्मिक-राजनीतिक दल ही नहीं अपितु यह सामाजिक लामबंदी इस्लामिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रमुख दल हैI पाकिस्तान की राजनीति में जमात-ए-इस्लामी का अस्तित्व इस बात का सूचक है कि पाकिस्तान में धार्मिक राजनीति एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकताIपाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में जमात-ए-इस्लामी को लोकतांत्रिक शासनकालों एवं सैनिक शासनकालों के दौरान विभिन्न उतार-चढ़ाव के दौर से गुज़रना पड़ाI यद्यपि लोकतांत्रिक शासनकाल में यह दल अधिक सक्रिय नहीं था किंतु सैनिक शासनकाल में इसके राजनीतिक पदस्थिति और वर्चस्व में वृद्धि देखी गईI पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में ज़िया-उल-हक़ और परवेज़ मुशर्रफ़ का सैनिक शासनकाल प्रमुख रहा हैI इस काल में जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आया और राजनीतिक पदस्थिति में विकास देखा गयाI

संकेत शब्द:पाकिस्तान, राजनीति,जमात-ए-इस्लामी, धर्म और राजनीति, सैनिक शासनकाल, धार्मिक-राजनीतिक दल

*शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

परिचय

तृतीय विश्व के देशों में दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारतऔरपाकिस्तान प्रमुख देश हैं,जहां एक ओर भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद से सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और साथ ही विभाजनके उपरांत पाकिस्तान की स्थापनाहुईI पाकिस्तान की स्थापना धर्म के आधार पर एक इस्लामिक राज्य के रूप में हुईIपाकिस्तान के निर्माण में धर्म एक महत्वपूर्ण कारक था और इसकी सफलता व एकता बनाये रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैI यद्यपि पाकिस्तान के निर्माण में धर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है जिनमें आर्थिक कारक व राजनीतिज्ञों के निजी हितों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कियाI किंतु इन सभी कारकों में पाकिस्तान आंदोलन में धर्म का स्थान अति-महत्वपूर्ण था और विभाजन को मूर्त रूप प्रदान करने में सर्वोपरि भी था (Weekes 2004:20-21)Iपाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में विभिन्न राजनीतिक दलों का विशेष महत्व रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों नें अहम भूमिका का निर्वहन किया हैI पाकिस्तान की राजनीति में राजनीतिक दलों के द्वारा निरंतर यह प्रयास किया गया है कि पाकिस्तान का राजनीतिक रूप से विकास किया जाए और विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं को अपनाया जाएI विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों, उदारवादी विचारों का अधिक विकास नहीं हो सका है किंतु फिर भी समय-समय पर यह देखा गया है कि अथक प्रयास अपनाये जाते हैं जिससे ना केवल राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके अपितु पाकिस्तान के स्वरुप में भी बदलाव आयेI पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान मुस्लिम लीग व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैI इन प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक राजनीतिक दलों का भी पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसने पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित किया हैI धार्मिक राजनीतिक दलों में मौलाना अबुल अला मौदूदी द्वारा स्थापित जमात-ए-इस्लामी एक अहम दल है व इसका पाकिस्तान की राजनीति में प्रमुख योगदान रहा हैIपाकिस्तान में इस्लामिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाला जमात-ए-इस्लामी महत्वपूर्ण दल हैIजमात-ए-इस्लामी मौलाना सैय्यद अबुल अला मौदूदी के मस्तिष्क की उपज है जिन्होंने इसकी स्थापनासन 1941 में विभाजन के पूर्व भारत में कीI उसकी स्थापना के पश्चात इकत्तीस वर्षों तक इसकी अध्यक्षता और संचालन किया (Nasr 1994:3)I यदि पाकिस्तान के धार्मिक दलों की बात करें तो स्पष्ट है कि जमात-ए-इस्लामी का पाकिस्तान की राजनीति में प्रभाव बढ़ा है और यह सक्रिय रूप से कार्यरत

हैI विभाजन के पश्चात मौदूदी पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए जहां उन्होंने इस्लामिक-राजनीतिक दल जमात-ए-इस्लामी का विकास एवं विस्तार कियाI मौलाना अबुल अला मौदूदी ने जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक वर्चस्व दिलाने एवं राजनीति में इसके प्रभाव को बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास कियाI यद्यपि जमात-ए-इस्लामी के विषय में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने पकिस्तान की स्थापना आंदोलन, जिन्ना और मुस्लिम लीग का विरोध किया था किंतु पाकिस्तान की स्थापना पश्चात् इसने वहां की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास कियाI विभिन्न सैन्य शासनों और नागरिक शासनों (लोकतांत्रिक सरकारों) के दौरान इसने राजनीति को प्रभावित कियाI प्रस्तुत लेख के अंतर्गत ज़िया-उल-हक़ और परवेज़ मुशर्रफ़ के सैनिक शासन में जमात-ए-इस्लामी की भूमिका का उल्लेख किया गया हैI

जिया-उल-हक़ का सैनिक शासनकाल (सन 1977 से 1988) और जमात-ए-इस्लामी

ज़िया वैचारिक परिवर्तन लाने के आलोचक थे, ज़िया स्वयं बहुत धार्मिक थे व सेना में मौलवीके रूप में प्रसिद्ध थेI ज़िया ने युवावस्था से ही इस्लामिक पुस्तकों का अध्ययन किया व इस्लामिक शिक्षा ग्रहण कीI ज़िया जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना मौदूदी के साहित्यिक कार्यों से बहुत अधिक प्रभावित थे जिसमें इस्लामिक राज्य की स्थापना की आवश्यकता पर बल दियाI सेना के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी ज़िया ने इस्लामिक संस्थानों की स्थापना कीI वह सैनिकों को प्रार्थना व उपवास रखने के लिए प्रेरित करते थे, सैनिकों और अधिकारियों के मध्य इस्लामिक साहित्यों के वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कीI ज़िया ने मौलाना मौदूदी के साहित्यिक कार्यों को परीक्षा में सम्मिलित करने का समर्थन किया (Nasr 2001:134)I

ज़िया ने उन सभी इस्लामिक व्यवस्थाओं को पुनः सक्रिय किया जो पतन की ओर उन्मुख थीI सबसे प्रमुख ज़िया ने धार्मिक मामलों के मंत्रालय और वक्फ़की पुनर्जीवित कियाI इसके साथ ही ज़िया ने इस्लामिक विचारधारा परिषद् को महत्वपूर्ण बना दिया जिसका कार्य था राज्य के नेताओं और संस्थाओं को इस्लामिक मामलों में सुझाव देनाI इस्लामिक विचारधारा परिषद् के सदस्यों में प्रसिद्ध उलेमा और इस्लामिक दल सम्मिलित थे, परिणामस्वरूप यह पाकिस्तान में इस्लामिक आंदोलन का वैध प्रतिनिधि थाI यह राज्य में इस्लामीकरण के उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम भी थाI इसने सामाजिक, आर्थिक, और कानूनी मामलों को इस्लामिक राज्य के आधार पर निर्मित किये जाने का प्रस्ताव रखाI पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित किये जाने का यह सुझाव समिति का था जिसने ज़िया को वैध कारण प्रदान किया कि वह समाज

तक अपनी पहुंच बनाये और सैनिक सेना के लिए स्थायित्व प्रदान कर सके (Nasr 2001:134)I ज़िया ने जमात को अपने सबसे महत्वपूर्ण समर्थक के रूप में देखा क्योंकि यह वर्ग भुट्टो की नीतियों का प्रबल विरोधी था (Nasr 2001:136)I

ज़िया-उल-हक़ के 1977-88 शासनकाल ने राष्ट्रपति की सत्ता और सेना के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई भूमिका को सुदृढ़ और सशक्त किया (Talbot 2012:119)I सन 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर राष्ट्रीय चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया गया और पाकिस्तान राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया जिसने क्रोध की भावनाओं को विभिन्न सार्वजनिक और राजनीतिकदलों के अंतर्गत संचारित कियाI हालांकि पाकिस्तान राष्ट्रीय संगठन में सेकुलर और उदारवादी राजनेता थे किंतु इस आंदोलन ने पूर्णत: धार्मिक रंग ले लियाI पाकिस्तान राष्ट्रीय संगठन ने यह दावा किया कि उसका घोषणापत्र कुरान पर आधारित है और पाकिस्तान के विभिन्न भागों से उसे समर्थन प्राप्त हो रहा थाI भुट्टो द्वारा धर्म का प्रयोग अपने आसपास की आबादी को अपने लक्ष्य के निकट लाना चाहते थे और अब वही उनके विरोधियों का उनके विरुद्ध यंत्र बन गयाI पाकिस्तान राष्ट्रीय संगठन जो 9 राजनीतिक दलों का संगठन था उसने मदरसों का प्रयोग किया जिससे आम आम-जनता की भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके तथा यह प्रभाव बना सके जिससे यह प्रतीत होने लगे कि वह निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा के कार्यान्वयन की दिशा में कार्यरत हैI नेताओं के द्वारा भुट्टो के सामाजिक व्यवहार की आलोचना की गई और यह आरोप लगाया गया कि उसने इस्लाम में आस्था खो दी हैI उलेमा के द्वारा इस्लाम को संरक्षित करने हेतु भड़काया गया ताकि जिहाद लाया जा सकेI इनके अनुसार इस्लाम दैत्य शासनव्यवस्थासे खतरे में हैIगठबंधन के द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया कि इस्लाम क्रियान्विति होगी और शरियत को निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा के रुप में लागू किया जाएगाIपाकिस्तान राष्ट्रीय गठबंधनके नवरतन ने राष्ट्रीय आवामी पार्टी के खान अब्दुल वली खासजो सेकुलरवाद और समाजवाद के लक्ष्यों पर आधारित थी, असग़र खां की तहरीक-ए-इंसाफ जो सेकुलरवाद का गुणगानकरती थी, मौदूदी की कट्टर इस्लामवाद पर आधारित जमात-ए-इस्लामी और मुफ़्ती मुहम्मद की जमात-उलेमा-ए-इस्लाम जो इस्लाम और शरियत के देवबंदी संस्करण पर आधारित था (Bano 2009:10)Iपाकिस्तान राष्ट्रीय गठबंधनके द्वारा सड़कों पर प्रचार-प्रसार किया गया और पुनः नए चुनाव कराये जाने की मांग की गई जिसके पश्चात सरकार को विपक्ष से बातचीत और इस संकट से निपटने के उपाय निकालने के लिए सामने आना पड़ा (Bokhari 2013:581)I

यह सभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के निरंकुश शासन के विपक्ष में संगठित हो गए थेI यद्यपि इनका इस्लाम का प्रयोग शक्ति प्राप्त करने हेतु यंत्र रुपी था जिसने दीर्घ और भयानक सैन्य तानाशाहीको जन्म दिया जो वैधता के लिए इस्लाम और रुढ़िवादी संस्करण पर आधारित थाI भुट्टो के द्वारा इस इस्लामवादियों के तुष्टिकरण हेतु देरीसे प्रयास किए और कृत्रिम तथा सांकेतिक साधनों का भी प्रयोग कियाI जैसे शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया, मद्य और जुआ पर प्रतिबंध इत्यादि किंतु विरोधियों के लिए यह सब बहुत देरी से हुआI ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और विपक्ष के मध्य कुछ घनिष्ठता के साक्ष्य मिलने लगे किंतु सेना प्रमुख ज़िया ने चयनित नागरिक सरकार का तख्तापलट कर दिया और अवसर प्राप्त करके जुलाई 5, 1977 को सैनिक शासन की स्थापना कीI यद्यपि एक ऐसे काल का प्रारंभ हुआ जिसमें इस्लाम ही अधिपत्यका वैचारिक यंत्र बन गया और इस नए वर्ग ने संपत्ति खाड़ी के देशों और सऊदी अरब से प्राप्त की (Bano 2009:11)I

ज़िया के काल में इस्लामीकरण के मानकों से संबंधित सर्वाधिक विवादित विषय सुन्नी और शिया के मध्य विवाद थाI ज़िया के द्वारा सुन्नी हनाफ़ी फ़िक को लागू करने पर बल दिया गया जिसका शिया समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से ज़कात के एकत्रीकरण के लिए व्यापक विरोध किया गया (Devasher, 2016:155)Iज़िया के काल में इस्लामीकरण तीव्र हो गया, ज़िया की छवि धार्मिक व्यक्ति की थी और ज़ुल्फ़िकार को इस्लाम विरोधी का रूप मिल गयाI ज़िया की नई नीतियों के कारण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान राष्ट्रीय गठबंधनके बीच सन 1977 में निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा को अपनाये जाने हेतु तनाव उत्पन्न हो गया और संविधान के सम्पूर्ण इस्लामीकरण ने ज़िया के मार्शल लॉलागू किए जाने का अवसर प्रदान कर दियाI ज़िया ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टीके विरुद्ध एवं सैनिक शासन को वैधता प्रदान करने के लिए इस्लामिक कार्ड का प्रयोग किया(Misra 2003:189)Iसन 1979 में भुट्टो की फांसी के बाद जमात और ज़िया ने सहयोगी आधार निर्मित कि भुट्टो की फांसी के उपरांत आरंभिक समय में जमात आक्रामक नहीं हुई तथा इसने ज़िया को स्थिति अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान कीI इसके अतिरिक्त सन 1979-1985 तक जमात के नेताओं ने जमात को सहयोग प्रदान किया क्योंकि ज़िया के द्वारा भी लोकतांत्रीकरण के मूल्यों और विधायिका में प्रत्यक्ष मताधिकार का विरोध किया गया एवं जमात ने भी इसका विरोध किया(Misra 2003:189)I

जनरल ज़िया के सामाजिक, आर्थिक और विधिक उपायों ने मौदूदी द्वारा उल्लेखित प्रतिबिंबित परिप्रेक्ष्य से प्रभावित थेI सन 1978 में राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक व्यवस्था को स्थापित किए जाने पर बल दियाऔर सत्ता प्राप्ति के पश्चात ही निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा को लागू किए जाने हेतु सार्वजनिक प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम

संचालित किएI पकिस्तान को इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रारंभिक मानकों में शरीयत शाखाओं की स्थापना करना थाI इसके समानांतर ही न्यायिक व्यवस्था जो सर्वोच्च न्यायालय की संघीय शरियत शाखाएं थी और इसके अतिरिक्त अन्य इस्लामिक न्यायालय भी स्थापित किए गएI विधिक और न्यायिक व्यवस्था को इस्लामिक रूप देने के लिए सन 1979 में हुदूद अध्यादेश लाया गयाI इन कानूनों ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनकी स्थिति को प्रभावित किया और अल्पसंख्यकों के नागरिकता के अधिकार को सीमित किया (Bano 2009:12)I

जनरल ज़िया-उल-हक़ की इस्लाम की व्याख्या देवबंदी जमात-ए-इस्लामी के धर्म के विचार से ली गईI यद्यपि सन 1985 में जनरल ज़िया-उल-हक़ के काल में संशोधन को संविधान का प्रमुख भाग बनाया गया और अनुच्छेद 2A संविधान में सम्मिलित किया गयाI 'इस्लामवाद' परियोजना की रूपरेखा मौलाना मौदूदी के राज्य की अवधारणा से लिया गया और जमात-ए-इस्लामी ही मात्र एक दल था जो ज़िया के शासनकाल में स्वतंत्र और मुक्त रूप से कार्यरत थाI ज़िया ने अर्थव्यवस्था को इस्लामवाद के दायरे से पृथक रखा क्योंकि पाकिस्तान के वित्तीय हितों के लिए वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से संलग्न रहना आवश्यक था (Bano 2009:11)Iपाकिस्तान दंड संहिता, आपराधिकदंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हुआ और अध्यादेश सन 1980, 1982 और 1986 लाया गया जिसके अंतर्गत पैगंबर मुहम्मद, मुहम्मद के परिवार के सदस्य, मुहम्मद के अनुयायी और इस्लामिक चिन्हों का अपमान करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गयाIइस अपराध के अंतर्गत दंड और कारागार दोनों का ही प्रावधान किया गयाI कानूनों के अंतर्गत सन 1984 काअध्यादेश महत्वपूर्ण है जिसमें विभिन्न कानून सम्मिलित किए गएI ज़िया के शासनकाल में बहुत से शिया मुसलमान और राजनेताओं की हत्या की गई और इनमें सर्वाधिकविशिष्टप्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की न्यायिक हत्या है (Bano 2009:12)I

ज़िया-उल-हक़ के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी के इस्लामिक मूल्यों की स्थापना और इस्लामिक न्यायिक व्यवस्था स्थापित किए जाने की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति हुई और इस दल के राजनीतिक परिवेश में वृद्धि देखी गईI यद्यपि ज़िया के सैनिक शासनकाल में पाकिस्तान का इस्लामीकरण के नए युग में प्रवेश हुआ और जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक सत्ता में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआI

परवेज़ मुशर्रफ का सैनिक शासनकाल (सन 1999 से 2008 तक) और जमात-ए-इस्लामी

मुशर्रफ़भी जिया की भांति दृढ़ अथवा रुढ़िवादी नहीं थे किंतु तब भी इन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति ही अपने सरकार के स्थायित्व व वैधता हेतु धार्मिक-दलों के सहयोग को महत्व दियाI इसी प्रक्रिया में मुशर्रफ़ ने धार्मिक दलों के गठबंधन मुताहिदा मजलिस-ए-अमल को विभिन्न रियायतें प्रदान की (Devasher 2016:153)Iजर्नल परवेज़ मुशर्रफ़ का सैनिक शासन ज़िया-उल-हक़ की तुलना में अयुब खां के सैनिक शासनव्यवस्था के अधिक निकट हैI दो दशक के बाद भी राज्य के मूल चरित्र में बहुत सीमित परिवर्तन ही देखा गया (Nasr 2001:159)I

यद्यपि 1999 में सैनिक सरकार सत्ता में आयी और शुरूआती समय में पाकिस्तान की राजनीति का पुनर्निर्माण करने की बात कहीI मुशर्रफ़ आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे और इनकी नीतियां ज़िया-उल-हक़ की इस्लामीकरण की नीतियों से भिन्न प्रकार की थीI वर्ष 2001 की 9/11 की घटना ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान और कश्मीर की विदेश नीति में नया मोड़ ले लियाI यह निर्णय लिया गया कि सेना वैचारिक के स्थान पर भौगोलिक रणनीतिक दूरदर्शिता के प्रति अधिक समर्पित होगीI अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भी मुशर्रफ़ ने अमेरिका का समर्थन किया और अमेरिका घनिष्ठ सहयोगी बन गयाI जो इस्लामिकों के लिए खुले रूप से समस्या उत्पन्न कर रही थी (Afridi, Tabi Ullah and Gul 2016:67)Iसेना प्रमुख जर्नल परवेज़ मुशर्रफ़ ने राष्ट्र को 19 सितंबर, 2001 को संबोधित करने के पश्चात जिन दो दलों ने पाकिस्तानी भूमि का अफ़गानिस्तान के विरुद्ध प्रयोग किये जाने को अस्वीकार किया उनमें एक दल था जमात-ए-इस्लामी जिसने इसका पूर्ण रूप से विरोध कियाI जमात की प्रतिक्रिया को तीन प्रकार से स्पष्टता से दर्शाया जा सकता है: प्रथम भर्त्सना, सितंबर 11, की शुरूआती दिनों में जमात के अध्यक्ष क़ाज़ी हुसैन अहमद ने विश्व व्यापार संगठन और पेंटागन पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की और इसे आतंकवादी कृत्य कहा और पीड़ितों के साथ सद्भावना व्यक्त कीIबाद में इसे मानवता के मूल्यों के विरुद्ध अपराध माना और इस बात बल दिया कि भी धर्म निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की अनुमति नहीं देताI द्वितीय, इसे इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र कहा, क़ाज़ी हुसैन अहमद ने आरंभिक समय में भी मीडिया द्वारा मुसलमानों और ओसामा बिन लादेन पर आरोपों की अप्रत्याशित प्रदर्शन का विरोध किया एवं इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र कहाI तृतीय, दृढ़ अमेरिकी-विरोधी विचार,आरंभिक समय से ही जमात ने इन घटनाक्रमों के लिए अमेरिका को उतरदायी मानाI सितंबर 11, 2001 की घटना अन्य व्यक्तियों की भांति ही जमात के लिए भी आश्चर्यचकित और उनके लिए यह मानना कठिन था कि एक सच्चे आस्था रखने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं (Grare 2001:4461-4462)I यद्यपि

सितंबर 11, 2001 की घटना ने विश्वपटल पर आतंकवाद के विषय को एक नये विध्वंसक समस्या के रूप में उजागर किया और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगाI

मुशर्रफ़ के द्वारा धार्मिक दलों के तुष्टीकरण का कार्य किया गया, मुशर्रफ़ का मानना था कि धार्मिक दल चाहे कितने भी अधिक प्रचलित और सुदृढ़ क्यों ना हो जाए उन्हें राष्ट्रीय सभा में कभी भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सकताI मुशर्रफ़ की चिंता मुख्य रूप से गैर-धार्मिक दलों जैसेपाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-(नवाज़) से थीI मुशर्रफ़ का मानना था कि भले ही नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ अधिक सफल ना हुई हो किंतु फिर भी आम जनता लोकतांत्रिक सरकार को ही चुनेगा क्योंकि वह नेतृत्व अधिक सुलझा हुआ है और प्रगतिशील प्रतीत होगाI अत: यह प्राकृतिक ही था कि मुशर्रफ़ धार्मिक दलों और अल्पसंख्यक गैर-धार्मिक दलों को समर्थन प्रदान करते थे(Misra 2003:191-192)Iयद्यपि जमात-ए-इस्लामी को शासन पद पर स्थित होने का अवसर नहीं मिला किंतु फिर भी यह पाकिस्तान की राजनीति में निरंतर सक्रिय है और अपना प्रभाव बनाये रखने में सफल सिद्ध हो रही है। जमात का पाकिस्तान की राजनीति में निरंतर प्रभाव बने होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसके पास अत्यधिक स्ट्रीट पावर (आम जनशक्ति है) जो महत्व को क़ायम रखती है। यद्यपि जमात पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करती है एवं शासकों तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपना प्रभाव बनाए रखती है।

पाकिस्तान में सेना की राजनीति में सहभागिता का तीन प्रमुख प्रभाव है, प्रथम, यह इस्लामिकों को कुशलता तक सीमित कर देता हैI द्वितीय, यह सभी दलों को यह अवसर प्रदान करता है कि सेना के साथ विवाद ना हो और वह लोकतांत्रिक रूप ले लेता हैI अंततः, सेना का राजनीति में अधिक हस्तक्षेप चुनावों, सहयोग, गठबंधन इत्यादि की नयी राजनीति को जन्म देता है (Nasr 2005:171-18)Iवर्ष 2002 में छ: धार्मिक दलों के गठबंधन मुताहिदा मजलिस-ए-अमल की स्थापना हुईIयद्यपि मुताहिदा मजलिस-ए-अमल को मुशर्रफ़ विरोधी अभियान का बहुत लाभ प्राप्त हुआ, और इनके द्वारा अमेरिका को दिए जा रहे समर्थन का भी निरंतर विरोध होने लगाI वर्ष 2007 तक यह गठबंधन कमज़ोर होने लगाथा इसके अतिरिक्त के अंतर्गत ही विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य ही विवाद उभरने लगेI जमात के आमिर क़ाज़ी हुसैन अहमद तानाशाही शासन के तीव्र आलोचक थे वहीं दूसरी ओर जमियत उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष फ़जल-उर-रहमान मुशर्रफ़ के शासन का समर्थन करते थे इस कारण भी गठबंधन में वैचारिक विभिन्नताओं का उदय होने लगाI यद्यपि मुशर्रफ़ 2007 में भी सत्ता में बने रहना चाहते थे और जहाँ एक ओर जमात ने 2008 के राष्ट्रीय सभा के चुनावों का

बहिष्कार किया और यह चुनावों के समर्थन में नही थी क्योंकि इनका मानना था कि चुनाव में धांधलीहोगी (Afridi, Ullah and Uzma Gul2016:71)I वर्ष 2008 में मुशर्रफ़ को सत्ता से निष्कासित किया गयाIयद्यपि जमात के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो यह सिद्ध होता है कि सैनिक शासनकालों में इसके प्रभाव में वृद्धि देखी गई और इसने सत्ता में सक्रियता से कार्य किया और अपने प्रभाव में विस्तार किया।जमात ने विभिन्न शासनकालों के दौरान राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और समय-समय पर यह राजनीतिक परिदृश्य में सक्रियता से कार्य कियाI ज़िया-उल-हक़ के काल में जमात के कार्यों में विस्तार हुआ और राजनीतिक स्तर पर इसके स्थिति अधिक सुदृढ़ व मजबूत हुई और परवेज़ मुशर्रफ़ के सैनिक शासनकाल जमात की कार्यशैली में तीव्र प्रगति हुईIपाकिस्तान में सेना का निरंतर वर्चस्व रहा है और सेना ही पाकिस्तान के राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों में निर्णायक की भूमिका का निर्वहन करता हैI यद्यपि पाकिस्तान में नागरिक-लोकतांत्रिक शासनव्यवस्था के अंतर्गत भी सेना अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव बनाने में सफल रही है और इसी प्रकार धार्मिक दल अपना प्रभाव बनाये रखने में सफल रहे हैंI

निष्कर्ष

पाकिस्तान के विषय में भी यह बात सिद्ध होती है कि विभाजन के इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान की राजनीति में इस्लाम निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और धर्म-राजनीति के स्वरुप को नया आयाम प्रदान किया है और यहां धर्म और राजनीति का अनूठा संगम पाया जाता हैI अतः यह गलत नहीं होगा कि प्रत्येक देश की राजनीति में धर्म किसी ना किसी रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व एक दूसरे को प्रभावित करते हैंI पाकिस्तान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वहां धर्म सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है तथा साथ ही संविधान, कानून, जीवन शैली इत्यादि से संबंधित भी है और उसके संचलान में अहम भूमिका निभाता हैI पाकिस्तान की राजनीति में जमात-ए-इस्लामी एक अभिन्न अंग बन गयाI यद्यपि यह सत्य है कि पाकिस्तान में इस्लाम का प्रभाव उसकी स्थापना के उपरांत से निरंतर बना हुआ है किंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जमात-ए-इस्लामी, जो पाकिस्तान की स्थापना आंदोलन का विरोध कर रहा था वह पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् से ही राजनीति में सक्रिय हो गई और महत्वपूर्ण धार्मिक-राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आयाIयद्यपि जमात के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो यह सिद्ध होता है कि सैनिक शासनकालों में इसके प्रभाव में वृद्धि देखी गई और इसने सत्ता में सक्रियता से कार्य किया और अपने प्रभाव में विस्तार किया।पाकिस्तान की राजनीति में इस्लाम (धर्म) का महत्वपूर्ण स्थान है

और इसकी राजनीति में धर्म की भागीदारी सक्रिय और निष्क्रिय एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से देखी जाती हैI पाकिस्तान की राजनीति में धर्म का वर्चस्व है व राजनीति धर्म के प्रभुत्व में ही संचालित होती हैI पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य शासन और लोकतांत्रिक शासन दोनों का ही सत्ता में निरंतर अंतराल में वर्चस्व रहा है किंतु यह स्वयं को धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पायाI यही कारण है कि धार्मिक-राजनीतिक दलों का अस्तित्व निरंतर बना हुआ हैI पाकिस्तान में सैनिक शासकों के द्वारा धार्मिक दलों का प्रयोग राजनीतिक यंत्र के रूप में किया गया है जिससे उनके शासन को स्थायित्व प्राप्त हो सकेI धार्मिक दल आम जनता की मनोभावनाओं को प्रभावित और आकर्षित करने का प्रमुख साधन है जिसका प्रयोग राजनीतिक दल भली प्रकार से करते हैंI यद्यपि पाकिस्तान में धर्म ना केवल लामबंदीकरण का ही माध्यम है अपितु यह राजनीति का प्रमुख अंग भी हैI

जनरल जिया उल हक का काल जमात-ए-इस्लामी में राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पहली बार हुआ था कि जमात-ए-इस्लामी को सत्ता के आने का स्पष्ट मौका मिला हो तथा इसे शक्ति प्राप्त हुई हो। प्रारंभ में इन दोनों के ही संबंध अच्छे रहे किन्तु बाद में तनाव बढ़ता ही गया। वहीं दूसरी ओर मुशर्रफ के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी ने समर्थन दिया तथा उनके विचारों से सहमति जताई। किन्तु जब मुशर्रफ ने धर्मनिरपेक्षीय सुधार संबंधी विचार प्रस्तुत किए तो जमात-ए-इस्लामी उनके विरोधी हो गए।

यदि जमात-ए-इस्लामी के 70 वर्ष के काल पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत से महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से होकर गुजरी।जमात-ए-इस्लामी के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस दल ने लोकतांत्रिक-नागरिकशासन की तुलना में सैनिक शासनकाल के युग में अधिक सफलता प्राप्त कीI सैनिक शासनकाल में इसकी सफ़लता का एक कारण यह भी है कि सत्ताधारी सैनिक शासक धार्मिक दलों को एक यंत्र के रूप में प्रयोग करते थे जिससे सैनिक शासन को वैधता प्राप्त हो और सैन्य शासन अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेI अर्थात् जमात-ए-इस्लामी सैन्य शासकों के लिए एक यंत्र रुपी साधन के रूप में कार्यरत हैंI

Reference

Ashutosh Misra, 2003, 'Rise of Religious Parties in Pakistan: Causes and Prospects',Strategic Analysis, Vol. 27, No.2.

Frederic Grare, 2001, 'Pakistan Islamic Threat to Stability: How Real?,' Economic and Political Weekly, December 2001.

Ian Talbot, 2012, Pakistan: A New History, Amaryllis: New Delhi.

Kamran Bokhari, 2013, 'Jama'at-i-Islami in Pakistan', in John H. Esposito and Emad El-Din Shahin (ed.), The Oxford Handbook of Islam and Politics, New York, Oxford University Press.

Manzoor Khan Afridi, Tabi Ullah and Uzma Gul, 2016, 'Electoral Politics of Jamat-e-Islami Pakistan (1987-2009)', Global Social Sciences Review (IGSSR), Vol. 1, No. 1, Spring 2016.

Masooda Bano, 2009, 'Maker of Identity: The Case of Jama'at-i-Islami in Pakistan and Bangladesh', Working Paper 34, Religious and Development Research Programme.

Seyyed Vali Reza Nasr, 1994, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i-Islami of Pakistan,I.B Tauris Publishers, London/New York,p.3.

Seyyed Vali Reza Nasr, 2001, Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power, Oxford University Press: New York.

Tilak Devasher, 2016, Pakistan: Courting the Abyss, Harper Collins: India.

Vali Nasr, 2005, 'The Rise of Muslim Democracy', Journal of Democracy, Vol. 16, No. 2, April, 2005.

Richard V. Weekes, 2004, Pakistan: Birth and Growth of a Muslim World, Royal Book Company: Karachi, Pakistan.